भारतीय किसान समुदाय को फुसलाने, कॉरपोरेट शिकंजे में फंसाने के लिए विश्व कॉरपोरेट पूंजीवादी शासक वर्ग द्वारा कैसे जाल बुना जा रहा है

I

1. विश्व आर्थिक मंच द्वारा सन् 2009 में कृषि के लिए नये दृष्टिकोण को परिभाषित किया गया था। इसमें ऐसी टिकाऊ खेती की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जो भोजन सुरक्षा, पर्यावरण स्थिरता तथा आर्थिक अवसर पैदा करे। इसके तहत 2050 तक प्रत्येक दहाई में हर क्षेत्र में 20 प्रतिशत सुधार का लक्ष्य रखा गया था।

2. इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसानों, सरकारों, सिविल सोसायटी तथा प्राइवेट सेक्टरों को लाभ पहुंचाने के नाम पर कृषि क्षेत्र में बड़ी तब्दीली की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

3. विश्व स्तर की कॉरपोरेट कंपनियां, जिनका खाद्य उत्पादन और उसके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण है, उनको कृषि के नये नजरिये में भागीदार बनाया गया है, ये कम्पनियां हैं : (i) एगको, (ii) आरचर डेनियल मिडलैंड, (iii) बी ए एड एफ, (iv) बेयर करोप साइन्स, (v) बुंगे, (vi) कोका-कोला कम्पनी, (vii) डी ए ओ, (viii) डू पोंट, (ix) जनरल मिल्स, (x) हाइनकिन, (xi) क्राफ्ट फूडज, (xii) मैट्रो, (xiii) मौनसेन्टो कम्पनी, (xiv) माइरसक, (xv) मोजाइक, (xvi) नैसले, (xvii) पैपसीको, (xviii) रोबोबैंक इन्टरनेशनल, (xix) सैबगिलर, (xx) सविस रे, (xxi) सिनजैन्टा, (xxii) टैक रिसोर्सेज, (xxiii) यूनीलिवर, (xxiv) वोडाफोन, (xxv) वालमार्ट स्टोर्स तथा (xxvi) यारा इन्टरनेशनल इत्यादि।

4. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक 1990 की दहाई के प्रारम्भ से मांग कर रहे थे कि राकफेलर फाउण्डेशन तथा फोर्ड फाउण्डेशन वाला संयुक्त राज्य अमेरिका में चल रहे कॉरपोरेट कृषि कारोबारी मॉडल की तर्ज पर भारतीय कृषि को लाया जाए। भारत में कोई भी सरकार देश के सबसे बड़े समूह किसानों पर हमला करने को तैयार नहीं थी जिनमें से बहुत सारे छोटी जोत की खेती के मालिक हैं।

5. नये कृषि दृष्टिकोण के अनुसार विश्व आर्थिक मंच में बनाई गई इंडिया बिजनैस काउन्सिल में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया गया : (i) बेयर करोप साइन्स, (ii) मोनसेन्टो, (iii) कारगिल, (iv) डोव एगरो साइन्स, (v) डूपोंट, (vi) लुइस ड्रेफस कम्पनी, (vii) वालमार्ट इंडिया, (viii) महिन्द्रा एंड महिन्द्रा, (ix) नैसले इंडिया लिमिटेड, (x) पैप्सिको इंडिया, (xi) रोबोबैंक इन्टरनेशनल, (xii) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, (xiii) स्विस रे सर्विसेज, (xiv) अडानी ग्रुप, (xv) यारा फर्टीलाइजर इंडिया, (xvi) 2030 वाटर रिसोर्सेज ग्रुप, (xvii) जैन इरिगेशन सिस्टम।

6. दुगुनी आमदनी वाले बैनर का जाल किसानों को फंसाने के लिए उछाला गया था, ताकि किसान भाईचारे को गुमराह करके कॉरपोरेट कम्पनियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार खेती की जमीनों को खरीदने की इजाजत दी जा सके, जिसके तहत बड़े खाद्य उत्पादन, प्रोसेसिंग फर्मों तथा कृषि में निर्यातक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निवेश किया जा सके।

7. किसानों की आमदनी को दुगुना करने के नवीन उपाय करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई, जिसमें सरकारी अधिकारी, प्रवासी भारतीयों तथा व्यापारियों के एक समूह— अडानी, पतंजलि आयुर्वेद, महिन्द्रा ग्रुप, इंडियन तंबाकू कम्पनी, बिग बास्केट, इत्यादि शामिल हैं। इस टास्क फोर्स ने विश्व आर्थिक मंच द्वारा बनाये गये नये कृषि दृष्टिकोण तथा इंडिया बिजनस काउन्सिल की हिदायतों के मुताबिक काम किया।

8. तीन किसान विरोधी कानून अन्तर्राष्ट्रीय से राष्ट्रीय स्तर तक हुई उपरोक्त समस्त दिमागी कसरत की उपज थे। परन्तु किसान आन्दोलन ने भारत सरकार को इन किसान विरोधी तथा कॉरपोरेट पक्षीय काले कानूनों को रद्द करने के लिए मजबूर कर दिया।

कलस्टर खेती रद्द किये गये किसान विरोधी तीन काले कानूनों का नया रूप है।

(क) भारत बागवानी फसलों में दुनिया भर का दूसरा बड़ा उत्पादक है। यह आम, केला, अनार, चीकू, नींबू तथा आंवला जैसे फलों का प्रमुख उत्पादक है।

(ख) सन् 2021-22 में बागवानी फसलों के नीचे रकबा बढ़ कर 27.74 मिलियन हैक्टेयर हो गया तथा लगभग 341.63 मिलियन टन का उत्पादन हुआ।

(ग) कलस्टर खेती का उद्देश्य भारतीय उत्पादों की विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में वृद्धि करके किसानों की आमदनी को बढ़ाना है।

(घ) इसमें उत्पादन, कटाई के बाद के प्रबन्धन, मार्केटिंग तथा निर्यात में बागवानी फसलों के लक्ष्यों के क्षेत्रीय संकेन्द्रण शामिल हैं।

(ड़) कलस्टर फार्मिंग की मुख्य विशेषताएं हैं :-सहयोग (किसान स्रोतों, ज्ञान एवं महारत को साझा करने के लिए मिल कर काम करना), स्रोतों (संसाधनों) का बंटवारा, दक्षता, कीट तथा रोग प्रबंधन, मार्केटिंग, निर्यात प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे का विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, छोटे किसानों के लिए बढ़ी हुई आमदनी, नौजवानों की संभाल (स्थानीय कलस्टर के काम में सहूलियत), सप्लाई चैन उपयोगिता (बाजारवाद के मुताबिक) आदि-आदि।

II

कलस्टर फार्मिंग की योजनाबंदी, तैयारी और अमल के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु

1. कलस्टर खेती को कुछ छोटी जोत वाले खेतों को मिलाकर बनाये गये खेतों के समूह (सैटेलाइट फार्म) को एक बड़े 'हब फार्म' के साथ जोड़ कर बनाया जाता है, जिसको कलस्टर कहा जाता है। इस हब फार्म के साथ एक ठोस उद्यमी समूह जुड़ा होता है, जिसके सदस्य लाभ और खर्च साझा करते हैं।

2. केन्द्र सरकार द्वारा पांच निजी फर्मों को तजरबे के लिए खास बागवानी फसलों की कलस्टर फार्मिंग में शामिल होने की इजाजत दी गई है। कलस्टर विकास प्रोग्राम पर 2200 करोड़ रुपये की लागत आयेगी! आकार के आधार पर प्रत्येक प्रोजेक्ट को औसतन 100 करोड़ रुपये दिये जायेंगे।

3. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, पश्चिमी बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, उत्तराखंड आदि राज्यों में 55 कलस्टर विचाराधीन है। इनमें से 5 लागू किये जा रहे हैं तथा 7 प्रोजेक्ट तजरबे के लिए किये जा रहे हैं!

4. देसाई ऐग्रीफुड्ज का 103 करोड़ रुपये का 'केला कलस्टर' प्रोजेक्ट अनरंगपुरा, आन्ध्रप्रदेश में विकसित किया जायेगा।

5. सहयादरी फार्मज का 205 करोड़ रुपये का 'अंगूर कलस्टर' प्रोजेक्ट नासिक, महाराष्ट्र में लगेगा।

6. मेघालय बेसिन मैनेजमेंट एजेन्सी का 52 करोड़ रुपये वाला 'हल्दी कलस्टर' प्रोजेक्ट पश्चिम जैंतीया पहाड़ियों में विकसित किया जायेगा।

7. एक आई एल इण्डस्ट्रीज सौपियां (जम्मू-कश्मीर) में 'सेब कलस्टर' विकसित करेगी।

8. प्रसाद सीड्स महबूबनगर (तेलंगाना) में 'आम कलस्टर' विकसित करेगा।

9. प्रोजेक्ट चमन (संगठित बागवानी मूल्यांकन तथा प्रबंधन) में भू-सूचना विज्ञान को उपयोग किया जायेगा। इन प्रोजेक्टों को पूरा करने और चालू करने की समय सीमा चार सालों की होगी। यह भू-सूचना विज्ञान का लाभ उठाने पर केन्द्रित है, जिसमें किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय आंकड़ों का उपयोग

करने तथा बागवानी क्षेत्र के समूचे प्रबंधन में सुधार करना शामिल है। यह किसानों को कुछ पहलुओं, जैसे कि मौसम के पैटर्न, मिट्टी में नमी के स्तर तथा फसलों में बिमारियों के प्रकोप के बारे में नवीनतम जानकारी भी प्रदान करता है।

10. कॉरपोरेट 'कलस्टर एग्रीबिजनस' के तहत वर्करों को आपस में साझा कर सकेंगे। इसके तहत योग्य व्यक्तियों को पक्की नौकरियों की पेशकश की जायेगी। यह नौकरियां ग्रामीण बेरोजगारी और प्रवास का हल प्रदान करेगी, जिनसे पंचायतें/नगरपालिकाएं निपटने की कोशिश कर रही हैं। स्थानीय विश्वविद्यालयों तथा विस्तार सेवाओं को बढ़ रहे खेतीबाड़ी/बागवानी क्षेत्र से लाभ मिलेगा। जहां एक तरफ विद्यार्थियों को रोजगार मिलेगा और दूसरी तरफ खोज और विकास की नीति को प्रोत्साहन मिलेगा।

11. एफ पी आई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेश) द्वारा फंड किये जाने वाले हब फार्मों को संगठित करने के लिए, एक संविधान, चेयरमैन, उप-चेयरमैन, सेक्रेटरी, उप-सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष तथा तीन कमेटी सदस्यों की अगुवाई वाली एक कमेटी बनानी आवश्यक होगी।

12. एफ पी आई का मुख्य जोर कलस्टर के माध्यम से शहरी तथा ग्रामीण किसानों की समर्थता को बढ़ाना तथा उनके लिए घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों को निम्नलिखित कदमों से खोलना है : (i) किसानों को फंड और प्रोत्साहन प्रदान करना, (ii) हब फार्म की वित्तीय सहायता करना, (iii) सैटेलाइट फार्मों को वित्तीय सहायता देना, (iv) पांच साल की निवेश समयावधि देना, (v) समस्त बिक्री तथा निवेश में से 30 प्रतिशत शेयर तथा मुनाफा लेना, (vi) समझौते के दौरान ही सालाना ब्याज दर तय होगी, (vii) जारी किये गये कर्जों का भुगतान तय की गई ब्याज दर तथा सहमति की समयावधि (मियाद) के अन्दर-अन्दर करनी होगी।

13. कलस्टर फार्मिंग/मोनो कल्चर बहुत बड़े दूर-दराज के बाजारों तक पहुंच के रूप में उभरा है, जिसको इसकी उच्च मशीनी बिजाई, कटाई, कम मजदूर आधारित, खादों व कीटनाशकों आदि के रूप में रसायन के उपयोग से अधिक लाभदायक बनाया जायेगा।

III

कलस्टर फार्मिंग या 'इंडस्ट्रियल मोनो-कल्चर' फार्मिंग, अधिक पूंजी, रासायनिक तथा तीव्र ऊर्जा क्षेत्र में तब्दील हो गई है। जिसका नतीजतन वातावरण/पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में बढ़ोतरी हुई है। खेती उत्पादों में गुण और मात्रा में नुकसान हुआ है तथा खर्चे अधिक बढ़ गये हैं। वातावरण को होने वाले नुकसानों को नीचे लिखे अनुसार देखा जा सकता है :-(i) जैव-जीवन प्रबंधन विज्ञान का खत्म होना - मोनो-कल्चर प्रणाली में विभिन्नता की कमी उन सारे कार्यों को खत्म कर देती है जिसमें कुदरत पौधों तथा मिट्टी को गुणवत्ता प्रदान करती है।

(ii) अधिक कृत्रिक सामग्री का उपयोग - प्राकृतिक जांच-परख तथा संतुलन को खत्म करते हुए, जो केवल एक विभिन्नता से भरा हुआ वातावरण प्रदान कर सकता है, जिसको हमने उत्पादन बढ़ाने तथा फसलों की सुरक्षा के लिए कृत्रिम रासायनिक खादों, कीटनाशकों, नदीननाशकों आदि की बड़ी मात्रा में प्रयोग करके खत्म किया है।

(iii) जीवाणुओं की बढ़ती प्रतिरोध क्षमता - कृत्रिम रासायनिक सामग्री के अत्यधिक निवेश ने फसलों पर हमला करने वाले जीवाणुओं की प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा दिया है।

(iv) मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट - जब ज्यादा से ज्यादा सघन (घनत्व) रसायनों का उपयोग किया जाता है तब मिट्टी के सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान होता है।

(v) जल दुरुपयोग - जमीन पर पेड़-पौधों की गैर मौजूदगी में वर्षा का जल बहाव बढ़ने से धरती के

पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए मिट्टी में नमी कायम रखने के लिए औद्योगिक मोनो-कल्चर/कलस्टर खेती को सिंचाई के लिए ज्यादा मात्रा में जल की आवश्यकता होती है।

(vi) जलवायु तब्दीली - हल जोतने, बिजाई, कटाई, छंटनी, पैकिंग तथा यातायात में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है जिसका परिणाम जलवायु तब्दीली में निकलता है।

IV

संक्षेप में

1. मोनो-कल्चर/कलस्टर खेती के तरीकों तथा जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों की चुनौती के मद्देनजर उत्पादकों एवं नीति निर्माताओं को औद्योगिक कृषि की धारणा की समीक्षा करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेन्सी नासा की चेतावनी के अनुसार जलवायु तब्दीली की तीव्रता अमेरिका में मक्की तथा सोयाबीन के उत्पादन को प्रभावित कर सकती है।

2. औद्योगिक खेती अब विश्व में प्रदूषण का मुख्य स्रोत बन रही है। कीटनाशक, खादें तथा अधिक जहरीले कृषि रसायन पानी, समुद्री वातावरण, हवा तथा मिट्टी को जहरीले बना रहे हैं।

3. औद्योगिक खेती गरीबी बढ़ा रही है तथा वातावरण को बिगाड़ रही है। अमेरिका तथा यूरोपीय देशों द्वारा अपनी खेती को प्रदान की जा रही सब्सिडियों से अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे विश्व भर में कृषि उत्पादों की कीमतें कम हो जाती हैं तथा कम आमदनी होने की वजह से विकासशील देशों में बहुत सारे उत्पादकों को खेती छोड़नी पड़ रही है या लालच में ज्यादा कृषि रसायनों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसलिए गरीब और विकासशील देशों का किसान समुदाय गरीबी, कर्जे तथा आत्म हत्याओं के जाल में फंस गया है।

4. औद्योगिक कृषि क्षेत्र हमारे ग्रह पृथ्वी के 69 प्रतिशत ताजा पानी की खपत करता है। रचनात्मक संभाल के तरीकों के बिना ताजा पानी की कमी और जलवायु संकट कृषि उत्पादन को झटका दे सकता है।

V

लोगों की अगुवाई में कृषि-जलवायु जोन के आधार पर सहकारी कुदरती खेती किसानों के सशक्तिकरण का एकमात्र रास्ता

1. कृषि अब दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग है। इसमें 1 बिलियन से अधिक लोग लगे हुए हैं तथा प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन डालर से अधिक का भोजन पैदा किया जाता है। चारागाह तथा फसली भूमि धरती की रहने लायक जमीन का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा है तथा अनगिनत किस्मों के जीवों को निवास और भोजन प्रदान करती है।

2. यदि कुदरती खेती टिकाऊ ढंग से प्रबंधित की जाती है, तो यह जीवों की नाजुक रिहायशगाहों को सुरक्षित और बहाल कर सकती है, जल क्षेत्रों की रक्षा में मदद कर सकती है, मिट्टी की सेहत और पानी की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है। जबकि असंतुलित अभ्यास का वातावरण से लोगों पर गंभीर नुकसानदायक प्रभाव पड़ता है।

3. मानवीय समाज, पर्यावरण, जैव-विवधता तथा विश्व आर्थिकता के साथ गहरे संबंध के कारण पर्यावरण एवं इसके अलग-अलग हिस्सों के बचाव, सार-संभाल एवं सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक नौकरियां व रोजगार सृजित हो सकते हैं।

4. यह कृषि क्षेत्र को विश्व भर में हमारे ग्रह धरती की सार-संभाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण मोर्चों में से एक बना देता है।